

केन्द्रीय प्रन्यासी मंडल एवं प्रबंध समिति बैठक कोची, केरल से
विश्व हिन्दू परिषद के महामंत्री डॉ० प्रवीणभाई तोगडिया का प्रेस वक्तव्य

प्रस्ताव— Hindi and English

हिन्दुओं का अधिकार एवं रोजगार छीनने के षड्यंत्र को बर्दाशत नहीं करेंगे।
हम किसी भी हिन्दू-ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओपन कैटोगिरी- की एक भी नौकरी या
अधिकार मुसलमान, ईसाई को नहीं देने देंगे।
ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को एक भी रोजगार नहीं देने देंगे
मुस्लिम आरक्षण संविधान के विरुद्ध है।
मजहब के आधार पर आरक्षण देश तोड़ने का षड्यंत्र है।

विश्व हिन्दू परिषद का वैश्विक प्रन्यासी मंडल एवं प्रबंध समिति सर्वसम्मति से, यूपीए सरकार द्वारा
सच्चर कमेटी की सिफारिशों की आड़ में, मजहब के आधार पर हिन्दू समाज की पिछड़ी जाति
(OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भाग में से 6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित
आरक्षण भाग में से भी कुछ भाग मुस्लिम समाज को देने का पुरजोर विरोध करती है।

मजहब आधारित आरक्षण भारतीय संविधान के विरुद्ध, भारत की एकता अखण्डता के लिए
खतरा तथा देश में अलगाववाद की भावना जागृत करने वाला है। इसके क्रियान्वयन से देश के पुनः
विभाजन का भी खतरा है। इसलिए प्रन्यासी मण्डल एवं प्रबंध समिति का यह अधिवेशन इस आरक्षण
का प्रबल विरोध करता है।

मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को पहले से ही हिन्दू पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटे में आरक्षण प्राप्त
है। मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को सरकारी अनुदान भी मिलता है फिर भी ऐसे संस्थानों में हिन्दू
SC/OBC युवकों के लिए आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मुस्लिम एवं ईसाइयों के
विकास के बहाने उनके तृष्टिकरण के लिये तीन-तीन आयोग बनाये गये हैं, फिर भी एक और आरक्षण
देने की सिफारिश केवल वोट बैंक की राजनीति ही है अतः संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

संविधान सभा में परिचर्चा के दौरान डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार
वल्लभभाई पटेल तथा श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने मजहब आधारित
आरक्षण की मांग का सर्वसम्मति से विरोध किया था, इतना ही नहीं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर
लाल नेहरू ने 27 जून, 1961 को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर "मजहब
आधारित आरक्षण" को नकार दिया था।

पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने से सम्पूर्ण हिन्दू समाज को भयंकर
परिणाम भोगने पड़ेंगे जैसे कि -

- पिछड़े जाति के कमजोर लोगों को बहुत भारी आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक हानि होगी।
- भविष्य में आबादी के अनुपात में मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए आरक्षण की मांग उठाई
जायेगी, जो देश को विभाजन के कगार पर खड़ा कर देगी।
- मजहबी उन्माद, वर्ग संघर्ष एवं दंगा आदि की घटनाएं बढ़ेंगी।
- पिछड़ी जाति के आर्थिक अनुदानों में से मुस्लिमों की हिस्सेदारी हो जाने के कारण पिछड़ा वर्ग
और अधिक कंगाल एवं बेरोजगार हो जायेगा।
- आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की वर्तमान भागीदारी व्यवस्था और उद्योग व्यापार में पिछड़े
वर्ग को मिलने वाली सहायता मुस्लिमों में बटेगी।

— अन्तरराष्ट्रीय मुस्लिम लाबी एवं ईसाई लाबी द्वारा भारत के हिन्दू युवकों को अपने-अपने मजहब में धर्मान्तरित करके अपनी जनसंख्या बढ़ाकर भारत को अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद का युद्धक्षेत्र बनाए जाने की संभावना बढ़ेगी और धर्मान्तरण को बढ़ावा मिलेगा। यह उपवेशन महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहता है कि मुस्लिम मजहब में जाति व्यवस्था मान्य नहीं है तो फिर मजहबी जातीय आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। महामहिम से अनुरोध है कि आप व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक, संवैधानिक हितों को ध्यान में रखकर इसमें हस्तक्षेप करके वर्तमान यू.पी.ए. सरकार को संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार मजहबी आरक्षण को निरस्त करने के लिये निर्देश दें।

आज ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है, भविष्य में अनुसूचित जाति का आरक्षण छीनकर मुस्लिम व ईसाई को दिया जायेगा। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ईसाई को दे दिया गया है अब भारत के संविधान में संशोधन करके मजहब के आधार पर मैरिट के हिन्दुओं का रोजगार छीनकर मुस्लिम व ईसाइयों को देने का षड्यंत्र की योजना है।

हमारी मांग है कि —

01. जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर कमेटी की सिफारिशें जो सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने वाली एवं अलगाववाद को बढ़ाने वाली है तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाय।
02. तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश आदि प्रान्तों में मुस्लिम समाज की गरीबी का बहाना बताकर वोट बैंक की घृणित नीति के अनुसार जो आरक्षण दिया गया है उसको भी रद्द किया जाए।
03. ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में से मुसलमानों को अलग 6 प्रतिशत आरक्षण न दिया जाय।
04. इस्लाम में जाति नहीं है तो आज 27 प्रतिशत ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों की जिस जातियां सम्मिलित है उनको भी हटाया जाय।
05. अनुसूचित जाति के आरक्षण से मुस्लिम व ईसाइयों को आरक्षण न दिया जाय।
06. अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से ईसाइयों को हटाया जाय।
07. भारतीय संविधान ने मजहब के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया है तो मजहब के आधार पर आरक्षण की सिफारिश एवं मांग करने वाले के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाय।

यह उपवेशन हिन्दू समाज का आह्वान करता है कि हिन्दू समाज में जन्मी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सभी मिलकर समस्त हिन्दू समाज की रोजी-रोटी छीनने वाली मुस्लिम/ईसाई वोट बैंक आधारित राजनीति को परास्त करें।

राष्ट्र की एकता अखण्डता में विश्वास रखने वाले सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं से विश्व हिन्दू परिषद का प्रन्यासी मण्डल अनुरोध करता है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में संगठित होकर इस सिफारिश को लागू किये जाने का पुरजोर विरोध कर आन्दोलन में सक्रिय सहभागी बने।

Dr. Pravinbhai Togadia-VHP Secretary General
Released Resolution of VHP Board of Trust All India Meeting at
Kochi, Kerala

UResolution

**We will not allow any job to be given to MUSLIM or CHRISTIAN, snatched from any Hindu,
be it OBC, SC, ST, NT or Open Category**

Muslim Reservation is Against the Constitution

Religion – Based Reservation is a Conspiracy to Divide Bharat once again!

The largest organization representing Millions of Hindus is VHP – Vishwa Hindu Parishad & we, the members of VHP All Board of Trustees & Governing Council Unanimously & strongly oppose the religion-based reservations to Muslims OR Christian in any form from any Hindu, be it OBC, SC, ST or Open category, now given by the Govt of India, in OBC's 27% quota per Sachhar Committee recommendations.

Religion-based reservations are big danger to Bharat's Unity & Integrity. The move to give religion – based reservations will further trigger separatism among Muslims & Christians. This will put Bharat on the verge of division again. This also is a violation of constitutional fundamental rights of Hindus. Therefore, all members of VHP All India Board of Trustees & members present in the All India Meeting here oppose the said move totally & completely.

Some Muslims are already a part of the OBC list. Muslim Educational Institutions get Govt grand & provision from OBC quota. Over 3 Commissions have been set up for Muslims & yet there is this move to give then religion – based quota from OBC. This is purely vote – Bank politics, which is against fundamental principles of Bharat's Constitution & also against any principle of natural justice.

Social leaders like Dr Babasaheb Ambedkar, Pundit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Shri Rajgopalachari etc had strongly & unanimously opposed to the very idea of religion – based reservations while the constitution was being written. Pundit Jawaharlal Nehru had also written a letter to all Chief Ministers on June 27, 1961 opposing to 'any community, cult or religion-based' reservations. (He mentions 'Sampradaay' in it)

By giving reservations to Muslims from the Backward classes' quota will have horrible consequences on Bharat & Hindus, namely:

1. Backward classes, socially downtrodden & the economically weakest from Hindus will have to suffer severe damage economically, educationally & politically.
2. Current 6% quota from OBC to Muslims will further enhance the demand by Muslims & Christians to give them reservations in all fields like education, jobs, loans, exemptions from various rules / regulations, politics etc based on their population percentage. This will permanently divide Bharat.
3. Religious extremism, rioting & communal conflicts will increase.
4. Snatching from Economic Subsidies meant for Backward classes to be given to Muslims will further make Backward classes economically bankrupt & unemployed.

5. Support currently given to economically backward classes & assistance they are currently getting in their trade & work will get snatched by Muslims disturbing the total trade & work systems in Bharat making Bharat economically volatile.
6. With the allurements of such proposed religion-based reservations, international Muslim & Christian lobbies will tempt Bharat's common youth to convert to Islam & Christianity. This will make Bharat a centre of Jihad / religious war-field & conversion will go up.

VHP All India Board of Trustees & Governing Council urge the Hon. President of Bharat that caste systems is not a part of Islam & Christianity therefore reservations meant for ancient traditional Hindu castes in Bharat should never be made available to Muslims or Christian, Hence, we urge Hon. President of Bharat to consider the larger national interest & social justice as prescribed in Bharat's constitution & elaborated by various judiciaries & intervene & prevent the UPA Govt from passing any bills / rules / laws / systems that will give reservations to Muslims or Christians either from the OBC / SC / ST / NT quota or independently.

We unanimously demand that

1. All recommendations by Rangnath Mishra Commission & Sachhar Committee should be totally rejected as they are detrimental to communal harmony & social justice in Bharat.
2. With the eye on political vote bank, making an excuse that Muslims are poor, religion – based reservations have already been given in some states like Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Bengal etc. We demand that they be withdrawn with immediate effect.
3. Either 6% or any quota should never be given to Muslims from OBC's 27% quota.
4. As Islam does not accept non-Islamic ancestors & therefore Hindu castes can not be in Islam. Therefore, all those so called castes of Muslims currently included in OBC list should also be de-listed immediately & their OBC quota be withdrawn.
5. Christians should not be given reservations from the quota of Scheduled Castes or otherwise.
6. Reservations given to Christians from Scheduled Tribes be immediately withdrawn.
7. Bharat's Constitution opposes religion –based reservations. Therefore, those who demand, promote or propagate reservations based on religion be prosecuted for treason.

Today, OBC quota is being snatched depriving the real rightful poor Hindus from getting justice; tomorrow Scheduled Castes quota will be snatched & will be given to Christian, ST reservation already given to Christians. The severe most Govt calamity further will be to amend the constitution to snatch educational facilities, jobs, loans & lives from all Hindus to be given to Muslims & Christians. This will make deserving merit youth to lose their jobs, livelihood & therefore lives.

We appeal to all Hindus of all castes, Scheduled Castes, Other Backward Class, Scheduled Tribes, Nomadic Tribes & all others to stand together as ONE & defeat the Muslim & Christian Vote Bank that has been hurting Hindus & snatching Roti & therefore livelihood of Hindus to be given to Muslims & Christians.

We appeal to all political parties, social organizations, NGOs, Media who believe in Unity, Integrity & Sovereignty of Bharat, to strongly oppose this move by the current Union Govt.

Hindus in Bharat together start an all Bharat public agitation against the conspiracy of making Hindus perish by the majority poor Hindu losing their roti by reservations to Muslims & Christians.

(SC: Scheduled Caste; OBC: Other Backward Class; ST: Scheduled Tribes; NT: Nomadic Tribes)

For further information, Contact: Dr Pravin Togadia: 098253 23406. drtogadia@gmail.com